



# NORTHERN RAILWAY MEN'S UNION

Registered, Recognised & Affiliated to : A. I. R. F. & H. M. S.

## HEAD QUARTERS DIVISION

Divisional Office :  
2 - E, Rause Avenue,  
Minto Bridge Rly. Colony,  
New Delhi - 110 002  
Phone : 22 - 991

Ref. No. NRMU/HQ/ Misc. ....

Dated 07-09-10 .....

मुख्य संवाददाता

### प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के समस्त ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2010 नई दिल्ली में सम्पन्न सम्मेलन में सर्वसम्मति से भारत सरकार के मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ दिनांक 7 सितम्बर 2010 को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया जिसमें आउटसोर्सिंग पर रोक, दिनों दिन बढ़ रही मंहगाई पर अंकुश लगाने, देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने, भारत सरकार द्वारा बनाये गए श्रम कानूनों का कठोरता से शत-प्रतिशत पालन कराने, और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। उक्त सम्मेलन में ओल इण्डिया रेलवे फेडरेशन द्वारा निर्णय लिया गया कि 7 सितम्बर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में यद्यपि तकनीकी कारणों से रेलवे सम्मिलित नहीं हो सका, फिर भी संघर्षरत कर्मचारियों को पूर्ण नैतिक समर्थन देने के उद्देश्य से उस दिन समस्त भारतवर्ष की रेलों पर धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आज दिनांक 7 सितम्बर 2010 उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय, बडौदा हाऊस के कॉपरनिक्स मार्ग स्थित गेट पर विशाल द्वार सभा का भोजनावकाश में आयोजन, एनआरएमयू हेडक्वार्टर मंडल एवं लेखा मंडल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जिसमें हेडक्वार्टर मंडल एवं लेखा मंडल के सभी शाखाओं के पदाधिकारियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में रेल कर्मियों ने भाग लिया। द्वार सभा को सम्बोधित करते हुए हेडक्वार्टर मंडल के मंडल सचिव श्री एस० के० त्यागी ने उन तमाम समस्याओं का उल्लेख किया जिनसे आम रेल कर्मचारी व्रस्त हैं और मंहगाई तथा बेरोजगारी आसमान छू रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं किया जा रहा है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, रेल कर्मचारियों की भी अनेकों जायज समस्याएं लम्बे समय से रेल मंत्रालय में लटकी हुई हैं। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखा मंडल के मंडल मंत्री श्री राकेश गुप्ता ने कहा कि एक तरफ रेलों में काम बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जिससे आम रेल कर्मचारी काम के बोझ से दबा हुआ है और तनाव के वातावरण में काम करने को मजबूर है। इस अवसर पर लेखा मंडल के सहायक मंडल मंत्री श्री एन० शशिधरण, लेखा के शाखा मंत्री श्री योगेश कोहेल, हेडक्वार्टर की शाखाओं के शाखा सचिव श्री देवेन्द्र पारचा, श्री टी० एस० राणा और शाखा अध्यक्ष श्री श्रीराम ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे।

मुख्य अतिथि के रूप में सभा को सम्बोधित करते हुए ओल इण्डिया मेन्स फेडरेशन एवं एनआरएमयू के महा मंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा ने अपने वक्तव्य में बताया कि देश की आजादी के बाद पहली बार सारे हिन्दुस्तान के ट्रेड यूनियन संगठन एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और 7 सितम्बर को पूरे देश में सरकारी उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के उपक्रम भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष कर रहे तमाम कर्मचारी बधाई के पात्र हैं जो बेरोजगारी, निजीकरण, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा दिनों दिन बढ़ती मंहगाई, श्रम कानूनों की अवहेलना, ठेकेदारी जैसे गंभीर मुद्दों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्षरत हैं अपने भाषण में श्री मिश्रा ने रेल कर्मचारियों के लंबित मांगों की ओर भी रेल मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा सरकार को चेतावनी दी कि यदि आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय रेलों पर आने वाले संघर्ष को टाला नहीं जा सकेगा। श्री मिश्रा ने बैठक में बताया कि माननीय रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद रेलवे बोर्ड भारतीय रेलों पर रेल कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आदेश जारी करने में आना-कानी कर रहा है जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और रेल प्रशासन को शीघ्र इसका निर्णय करने की चेतावनी दी। अपने भाषण के अन्त में महामंत्री ने रेल कर्मचारियों को एनआरएमयू एवं एआईआरएफ के बैनर तले संगठित रहने का आह्वान करते हुए भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की।

सुशील  
(एस.के. त्यागी)  
मंडल मंत्री